पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International
हमारा मुख-पत्र
वर्ष 15, अंक 3/2014

बैंकिंग सेवाओं में वित्तीय उत्पादों के विक्रय पर अंकुश जरूरी - वी.जी. सेकर

बैंकिंग सेवाएं केवल मात्र विश्वास पर कायम है और कायम रहनी चाहिए तथा गैर वाजिब तरीके से उपभोक्ताओं को विश्वास में लेकर वित्तीय उत्पादों को विक्रय करने से संबंधित शिकायतों की बढ़ती हुई संख्या ने समूची बैंकिंग प्रणाली में विश्वास को झकझोरा है।

'कट्स' द्वारा जयपुर में 18 सितम्बर 2014 को 'भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के ड्राफ्ट चार्टर' पर आयोजित एक परिचर्चा में भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबन्धक (बैंकिंग निगरानी) वी.जी. सेकर ने मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए उक्त विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट चार्टर में गलत तरीके से विक्रय किए गए वित्तीय उत्पादों का भी उल्लेख हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार की शिकायतों पर भविष्य में सख्ती बरती जाएगी। सेकर ने भारतीय रिजर्व बैंक के एक नियामक के रूप में उपभोक्ता हितार्थ कार्यों पर प्रकाश डाला।

परिचर्चा में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में सचिव एवं उप महाप्रबन्धक ए.बी.दास ने लोकपाल के समक्ष गैर तरीके से विक्रित वित्तीय उत्पादों से संबंधित शिकायतों का ब्योरा दिया तथा लोकपाल द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी दी। दास ने अपने उद्‌बोधन में सभी बैंकों का आह्वान किया कि वे इस संबंध में उपभोक्ताओं का विश्वास पुनः कायम करें क्योंकि उनका अस्तित्व उपभोक्ताओं के प्रति सेवा भाव तथा विश्वास पर ही कायम है।

जॉर्ज चेरियन, निदेशक, 'कट्स' ने अपने प्रारम्भिक उद्‌बोधन में 'कट्स' का परिचय देते हुए संस्था द्वारा वित्तीय सेवाओं में उपभोक्ता संरक्षण के प्रति समर्पण की भूमिका का वर्णन किया। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए उपभोक्ता अधिकारों पर नागरिक चार्टर को एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इसके सफल क्रियान्वयन से 'क्रेता सावधान' से 'विक्रेता सावधान' के सिद्धान्त को न केवल मजबूती मिलेगी, अपितु इसमें वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में एक क्रांति भी आएगी। हालांकि चेरियन ने चार्टर के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्ययोजना के अभाव पर चिंता जताई तथा बैंकों को इस कार्य को अंजाम देने का आह्वान किया।

परियोजना समन्वयक अमरजीत सिंह ने अपने प्रस्तुतिकरण द्वारा ड्राफ्ट चार्टर के मुख्य बिंदुओं का उल्लेख करते हुए उनका वर्णन किया तथा 'कट्स' द्वारा हाल ही में शुरू हुई 'राईट टू चॉइस ऑफ कन्ज्यूमर्स ऑफ फाईनेन्सियल सर्विसेज' परियोजना का भी उल्लेख किया, जो कि गैर तरीके से विक्रित वित्तीय उत्पादों पर आधारित है।

भारतीय रिजर्व बैंक के ड्राफ्ट चार्टर में निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार, पारदर्शिता का अधिकार, निष्पक्ष व निष्कपट लेन-देन का अधिकार, निजता का अधिकार, शिकायत निवारण एवं क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार नाम से पांच अधिकार वर्णित है। रिजर्व बैंक द्वारा इस चार्टर पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

इस परिचर्चा का उद्देश्य विभिन्न भागीदारों द्वारा चर्चा में भाग लेकर अपने-अपने सुझाव देना था, जिसको कि 'कट्स' द्वारा एकीकृत कर एक वृहत सुझाव दस्तावेज द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत करना है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में दीपक सक्सेना, वरिष्ठ कार्यक्रम समन्वयक ने सभी संभागियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में जयपुर स्थित विभिन्न बैंकों के अधिकारियों, वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण पर कार्य करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों उपभोक्ता कार्यकर्ताओं व मीडिया सहित कुल 35 संभागियों ने भाग लिया।

इस अंक में...

- कहां है गरीबी उन्मूलन का पैसा? 3
- भ्रष्टाचार कैंसर से भी खतरनाक – मोदी ... 5
- चिंताजनक है बिजली चोरी–गोयल 8
- बिजली खर्च बदलेगा पानी की दरें 9
- बनेगा महिला टेक्नोलॉजी पार्क 10

जयपुर में होगी 'कट्स इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसी सेन्टर' की स्थापना

आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि 'कट्स' इंटरनेशनल द्वारा जयपुर स्थित जगतपुरा क्षेत्र में 'कट्स इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसी सेन्टर (सिप्पोलक)' स्थापित किया जाएगा। करीब 5 हजार स्क्वॅायर मीटर में बनने वाला यह सेन्टर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञताओं से परिपूर्ण एक राष्ट्रीय केन्द्र होगा। 'कट्स' के अध्यक्ष एम. एल. मेहता व महामंत्री प्रदीप एस. महता ने उम्मीद जताई कि केन्द्र का पूर्णरूप से सुसज्जित भवन वर्ष 2016 के अन्त तक तैयार हो जाएगा। प्रस्तावित केन्द्र में आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रदर्शनी स्थल, संगोष्ठी कक्ष, सभागार, पुस्तकालय, व्यापार कक्ष, स्वास्थ्य और फिटनेस केन्द्र, तरणताल, अतिथि कक्षों तथा भोजनालय की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

इस केन्द्र की गतिविधियों का औपचारिक रूप से शुभारम्भ किया जा चुका है। केन्द्र सुयोग्य, अनुभवी और दिग्गज विद्वानों द्वारा संचालित किया जा रहा है। पिछले दिनों भारत सरकार के योजना आयोग के सुधार व नवीनीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर शोध किया गया है और गोष्ठियों की अगुवाई करते हुए केन्द्र सरकार को तत्सम्बन्धित रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है।

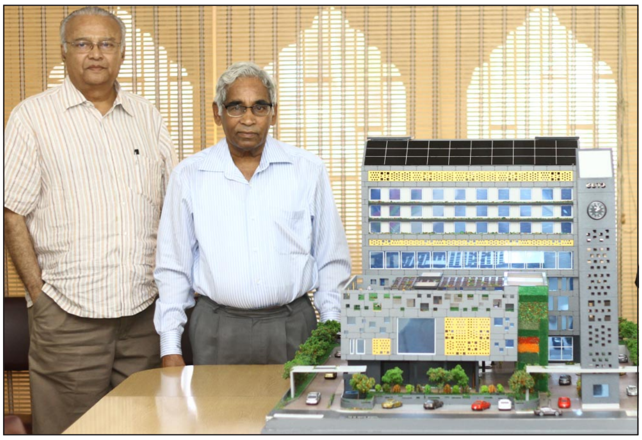

निकट भविष्य में यह केन्द्र प्रशासनिक सुधार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारिता क्षेत्र, विदेश सम्बन्ध, और शिक्षा प्रणाली में सुधार जैसे अनेक क्षेत्रों में आम नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए शोध कार्य और नीति निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएगा। वर्तमान में सिप्पोलक की सदस्यता की प्रक्रिया जारी है। आवेदन पत्र सिप्पोलक की वेबसाइट www.cippolc.in से प्राप्त किया जा सकता है।

खुले में कचरा फेंकना जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या

'कट्स' सर्वेक्षण पर एक नजर

कार्यक्रम में परियोजना के द्वितीय चरण में किए गए सर्वे में सामने आए मुख्य तथ्यों का प्रस्तुतिकरण करते हुए परियोजना समन्वयक अमरदीप सिंह ने बताया:

- *जयपुर शहर में 49 फीसदी लोग कचरे को खुले में फेंकते हैं तथा 13 फीसदी ही लोग कचरा डिपो की सुविधा का लाभ उठा पाते हैं।*
- *जिन वार्डों में नागरिक विकास समितियां हैं वहां 86 फीसदी इनसे लाभान्वित हुए हैं, जो उनकी उपयोगिता और सक्रियता को प्रदर्शित करते हैं।*
- *करीब 88 फीसदी जनसंख्या को अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल के मैदान या पार्क उपलब्ध नहीं हैं।*
- *सर्वे में 50 फीसदी लोगों ने बताया कि नगर निगम में की गई शिकायतों पर कोई प्रभावी समाधान नहीं होता। शहर में 75 फीसदी लोगों को आवारा पशुओं से सामना करना पड़ता है।*

'कट्स' द्वारा एशिया फाउण्डेशन के सहयोग से चलाई जा रही 'माईसिटी' परियोजना के तहत 28 अगस्त 2014 को जयपुर में आयोजित 'एडवोकेसी व प्रचार प्रसार बैठक' में जयपुर की महापौर ज्योति खण्डेलवाल ने मुख्यवक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विकास के साथ-साथ समस्याएं भी निरन्तर बढ़ती रहती हैं। स्थानीय निकायों में वार्ड कमेटी का गठन एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके लिए मुन्सिपल एक्ट में भी प्रावधान है।

कोटा की महापौर डॉ. रत्ना जैन ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कोटा शहर में मोबाइल टेक्नोलॉजी द्वारा किए गए कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने बताया कि इसके जरिए नागरिक न केवल सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।

इससे पूर्व अपने परिचयात्मक उद्बोधन में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने अतिथियों व सहभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि संविधान के 73वें संशोधन को लागू किया जा चुका है, परन्तु 74वें संशोधन को लागू करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है, जिसमें वार्ड सभाओं का प्रावधान है।

कार्यक्रम में डॉ. सागर परसाई, राष्ट्रीय प्रतिनिधि, एशिया फाउण्डेशन, दिल्ली ने अपने सम्बोधन में कहा कि सर्वे के परिणामों पर बहस की जा सकती है, परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि बहस में उभरे मुद्दों का समाधान किया जाए। इस अवसर पर मनीष पारीक, उपमहापौर, जयपुर नगर निगम, राव राजेन्द्र सिंह, विधायक तथा अन्य गणमान्य अतिथि, पार्षदगण, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा नगर निगम के अधिकारीगण उपस्थित थे।

मुर्दों ने की मजदूरी और उठाया भुगतान

जो दुनिया छोड़ गए लेकिन मजदूरी करने आए और अपना मेहनताना भी लेते रहे। कागजों में मनरेगा के तहत उनकी उपस्थिति दिखाकर लाखों रुपए का घोटाला किया गया।

उदयपुर जिले की गोगुंदा पंचायत समिति क्षेत्र के छाली पंचायत के रिकॉर्ड देखें तो यह माना जाएगा कि मरने के बाद भी लोग काम करते हैं। इनमें चन्ना, उमरिया निवासी लसूड़ी और हेमा जैसे कई लोग वर्ष 2010 से पहले ही दुनिया को अलविदा कह गए थे, लेकिन ग्राम पंचायत प्रशासन ने उनसे मजदूरी करवाने से गुरेज नहीं किया। उनके नाम से उपस्थिति दिखा कर भुगतान उठाया गया।

गांव वालों का कहना है कि इस तरह दर्जनों मृत लोगों को मनरेगा में काम पर दिखाकर लाखों रुपए उठा लिए गए। प्रारम्भिक जांच में सरपंच रामसिंह सहित सचिव, रोजगार सहायक सवाराम भील तथा दो मेट दोषी पाए गए हैं। *(रा.प., 22.08.14, 27.08.14)*

मोहलत देकर पहुंचाया फायदा

राज्य में राशन कार्ड बनाने वाली फर्मों की लापरवाही पर जुर्माना वसूलने की बजाय सरकारी मोहलत देकर करीब 8.80 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया जा रहा है। सितम्बर 2012 में 1.76 करोड़ राशन कार्ड बनाने का काम शुरू हुआ था। अनुबंध के तहत फर्मों को, इसे 4 से 6 माह में पूरा करना था। देरी पर फर्मों से प्रति राशन कार्ड पांच रुपए जुर्माना लिया जाना था।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जुर्माना वसूलने के बजाय कार्ड बनाने की अवधि बढ़ा दी। पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकारों का फर्मों पर 'मेहरबानी' का सिलसिला जारी है। *(रा.प., 27.08.14)*

करोड़ों खर्च, नहीं बढ़ी विकास दर

राज्य की विकास दर को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में 2007 से 2012 के बीच करीब 2129 करोड़ 97 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन फिर भी विकास दर नहीं बढ़ सकी।

यह खुलासा हुआ है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2007 से 2012 के दौरान कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत वार्षिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य था। इसके जरिए सकल घरेलू राज्य उत्पाद (जीएसडीपी) में भी विकास दर बढ़ाने का लक्ष्य था। *(रा.प., 21.07.14)*

पेंशन पाने के लिए हो गए बूढ़े

वृद्धावस्था पेंशन योजना को कुछ अपात्र लोगों ने सरकारी नुमाइंदों की मिलीभगत से अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। इस फर्जीवाड़े में 39 से 52 साल की आयु के कुछ लोग कागजों में 55 से 58 साल के बुजुर्ग बनकर 500 रुपए प्रति माह की पेंशन उठा रहे हैं। जांच में लोगों के परिचय पत्र के आधार पर इस फर्जीवाड़े की पुष्टि की गई। फर्जीवाड़े में अभी कुछ ही मामले सामने आए हैं।

जांच होने पर बंदरबांट के ऐसे कई मामले सामने आएंगे। विभिन्न पेंशन योजनाओं में इस तरह की गड़बड़ी को देखते हुए वर्तमान सरकार ने इसकी जांच भी शुरू की लेकिन जांच में समय लगने व लोगों को पेंशन नहीं मिलने से हुई नाराजगी को देखते हुए फिलहाल सरकार ने पेंशन देने के आदेश जारी कर दिए। *(रा.प., 04.09.14)*

निगम को लगा करोड़ों का चूना

नगर निगम क्षेत्र में विज्ञापन के लिए होर्डिंग व यूनिपोलों की समय पर नीलामी करने में निगम के अधिकारियों की नाकामी के कारण 1.92 करोड़ रुपए का चूना लगा। निगम के अधिकारी अभी तक इस राशि की संबंधित फर्मों से वसूली नहीं कर पाए हैं।

इसके लिए निगम अधिकारियों ने विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस और स्मरण-पत्र भी भेजे हैं, लेकिन विज्ञापन एजेंसियों ने अभी तक कोई भुगतान नहीं किया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विज्ञापन एजेंसियों ने विज्ञापन नहीं हटाए और समय खत्म होने के बाद भी अपने विज्ञापनों को जारी रखा। *(दै.न., 11.08.14)*

इंजेक्शन खरीद में करोड़ों का घोटाला

निःशुल्क दवा योजना की सूची में शामिल सांप के काटने पर काम में आने वाले पॉलीवेलेट (एंटी स्नेक वैनम) लिफोलाइज इंजेक्शन की खरीद प्रकिया में 13 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इंजेक्शन के लिए केन्द्र सरकार की मूल्य नियंत्रण सूची को धता बताते हुए एक कंपनी को इसकी अधिकतम कीमत 410 रुपए के बजाए 662 रुपए पर खरीद के आदेश जारी कर दिए। विभाग हर साल 5 लाख इंजेक्शन खरीदता है। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से यह घोटाला सामने आया। मामले का खुलासा होने के बाद इंजेक्शनों के बाजार में बिकने जैसी अनेक गड़बड़िया भी सामने आ रही हैं। *(रा.प., 17, 18.07.14, 04.08.14)*

कहां है गरीबी उन्मूलन का पैसा?

वित्त विभाग ने राजस्व घाटे को कम दिखाने और सरकार की कमाई को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने के चक्कर में गरीबी उन्मूलन निधि कोष का पैसा राजस्व खाते में डाल दिया।

इसका खुलासा राज्य विधानसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान विधायक राव राजेन्द्र सिंह ने किया। साल 2007 में एफआरबीएम एक्ट के तहत राज्य सरकार ने गरीबी उन्मूलन निधि और विकास निधि का कोष बनाया।

गौरतलब है, गरीबों के विकास के नाम पर बने इस कोष से 2009 तक 850.96 करोड़ रुपए डाले गए। राव राजेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार ने इस फंड का इस्तेमाल ही नहीं किया। वित्त विभाग ने एक्ट में संशोधन कर चालाकी से इस पैसे को राजस्व में डाल दिया। इसी तरह अकाल राहत कोष में भी गड़बड़ी हुई है। *(दै.भा., 31.07.14)*

वित्तीय सहायता में करोड़ों की हेरफेर

राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयूज को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कहीं हिसाब-किताब दर्ज नहीं है। विधानसभा पटल पर रखी गई सीएजी रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 31 मार्च तक राज्य सरकार की ओर से पीएसयूज को अलग-अलग मदों में 93000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई, लेकिन पीएसयूज के खातों से जब इस रकम का मिलान किया गया तो वहां पर राशि सिर्फ 91000 करोड़ रुपए ही दर्शायी गई।

सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है कि 19 पीएसयूज के खाते और वित्त विभाग के लेखों के मिलान में 2000 करोड़ रुपए की रकम की हेर-फेर सामने आई है। इनमें से 1219 करोड़ रुपए का अंतर बैंक गांरटी, 936 करोड़ रुपए का ऋण में फर्क और 15 करोड़ रुपए का अंतर पूंजी निवेश में देखने को मिला है। *(दै.भा., 21.07.14)*

जांच में खुली दवा योजना की पोल

राज्य सरकार के मूल्यांकन संगठन की ओर से निःशुल्क दवा योजना पर हाल में जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की कमी और मौजूदा अस्पतालों में स्टाफ की कमी के चलते निःशुल्क दवा योजना का लाभ आमजन को सही रूप में नहीं मिल पा रहा है।

मरीजों के अनुपात में दवा वितरण केन्द्रों की संख्या में कमी और दवा केन्द्रों पर सभी दवाएं समय पर उपलब्ध नहीं होने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। 2 अक्टूबर 2011 से मार्च 2013 तक की अवधि में बतौर उदाहरण बूंदी व डूंगरपुर जिले के अस्पतालों में किए गए मूल्यांकन में ऐसी कई अन्य कमियां भी सामने आई हैं।

हालांकि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने दवाओं की उपलब्धता की कमी को स्वीकार करते हुए कहा कि दवाओं की कमी की सूचनाएं पूरे देश से मिल रही है, कमियों को जल्द दुरुस्त किया जाएगा। *(रा.प., 30.09.14)*

लापरवाही से हुआ राजस्व को नुकसान

आम लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पाली जिले में शुरू की गई जवाई पाइप लाइन योजना में अधिकारियों की लापरवाही के कारण नौ करोड़ रुपए से भी अधिक के राजस्व का नुकसान हुआ है। इसके अलावा लोगों को समय पर पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो सका।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार पाली जिले में 531 गांव व 10 कस्बों को पेयजल आपूर्ति के लिए राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवरेज प्रबंधन मंडल तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की नीति नियोजन समिति को काम सौंपा गया था। रिपोर्ट में खुलासा किया है कि अधिकारियों ने बिना पड़ताल के जवाई व हेमा बांध पर पम्पिंग स्टेशनों की स्वीकृति दे दी बाद में निर्माण नहीं किया गया। *(दै.न., 04.08.14)*

फर्जी परिवारों के नाम से उठा गेहूं

कोटड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में पिछले कई सालों से बीपीएल परिवारों को वितरित करने वाले गेहूं की आपूर्ति करने वाली ठेकेदार फर्म लगभग एक चौथाई अधिक गेहूं उठा रही है। रसद विभाग परिवारों की संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन कर रहा है बदले में हर माह उसे करीब 25 प्रतिशत तक कम गेहूं वितरण का हिसाब दिया जा रहा है।

उदयपुर जिले की पंचायत समिति कोटड़ा में वर्ष 2008-09 से अंत्योदय परिवारों की संख्या 5402 है। इन परिवारों के लिए 1890.7 क्विंटल गेहूं का आवटंन होना चाहिए। रसद विभाग ने इस पंचायत समिति क्षेत्र में मार्च 2009 से 6978 परिवारों को आधार मान कर 2242.3 क्विंटल गेहूं का आवंटन कर रहा है। अधिक उठाया जा रहा गेहूं कहां जा रहा है इसकी उच्चस्तरीय जांच आवश्यक है। *(रा.प., 21.09.14)*

सरकार भूल गई एंबुलेंस खरीदकर

एक साल पहले राज्य सरकार ने 100 एंबुलेंस खरीदी लेकिन खरीदकर भूल गई। यह सरकारी लापरवाही और लालफीताशाही की एक बानगी है। ये एंबुलेंस आठ करोड़ रुपए में खरीदी गई थीं। मकसद था-लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना व सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को बचाना।

राज्य सरकार ने 100 एंबुलेंस अक्टूबर 2013 में खरीदी थी। कंपनी से इनकी तुरंत डिलीवरी भी हो गई लेकिन यह एंबुलेंस पिछले एक साल से अजमेर रोड़ पर टाटा मोटर्स के एक अहाते में धूल फांक रही हैं। हैरानी यह है कि इनके बारे में न सरकार के मंत्री को मालूम है और न ही किसी अफसर को। इन्हें ढूंढ निकाला दैनिक भास्कर ने। डॉक्टरों का कहना है कि एक एंबुलेंस 12 माह में 1200 से ज्यादा जानें बचाती है। *(दै.भा., 30.09.14)*

किसको सुनाएं अपनी पीड़ा?

पीडितों की सुनवाई के लिए गठित किए गए आयोग खुद अपनी पीड़ा से गुजर रहे हैं। महीनों बीतने के बाद भी राज्य सरकार ने इनमें अध्यक्ष और सदस्य नहीं लगाए हैं। इनका हाल भी सरकारी दफ्तरों का जैसा हो गया है, जहां लोगों को टरकाने का काम किया जा रहा है।

राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में काफी समय से अध्यक्ष के पद खाली हैं। वहीं निशक्तजन आयुक्तालय में आयुक्त का पद रिक्त पड़ा है। राज्य सूचना आयोग में भी सूचना आयुक्त नहीं होने से सिर्फ मुख्य सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं। इससे यहां अपीलों का अम्बार बढ़ता जा रहा है।

सरकार ने आयोगों में खानापूर्ति के लिए कई जगह अध्यक्ष की जगह सदस्य को अध्यक्ष के अधिकार दे रखे हैं तो कुछ जगह सरकारी अधिकारी कार्यवाहक अध्यक्ष का काम देख रहे हैं। *(रा.प., 23.09.14)*

भ्रष्टाचार कैंसर से भी खतरनाक – मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की घोषणा करते हुए कहा है कि न मैं खुद खाऊंगा, न खाने दूंगा। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों से राज्यों और केन्द्र में हो रहे भ्रष्टाचार ने देश के विकास को प्रभावित किया है।

हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, ताकि धन का इस्तेमाल गरीबों के कल्याण और विकास के लिए किया जा सके। कश्मीर में 45 मेगावाट बिजली परियोजना का उद्घाटन और लेह-कारगिल-श्रीनगर बिजली पारेषण लाइन की आधारशिला रखने के बाद जनसभा में यह घोषणा करते हुए कहा कि हमारे पास सब कुछ है, इसके बावजूद देश में गरीबी बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। यह देश को तबाह करने वाली बीमारी है। देश को इससे मुक्त करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन उसके लिए मुझे आपका (जनता का) आशीर्वाद चाहिए।

मोदी ने हरियाणा में नेशनल हाइवे को फोरलेन बनाने के प्रोजक्ट का शिलान्यास करते हुए आमजन को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आह्वान किया। *(रा.प., दै.भा., दै.न., 20.08.14)*

दागी कार्मिकों को अभयदान क्यों?

राज्य सरकार ने काली कमाई करने वाले मामलों में फंसे 29 सरकारी कार्मिकों को अभयदान दे दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इन्हें पद के दुरुपयोग का दोषी माना था, लेकिन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लगे प्रमुखों ने उनके खिलाफ चालान पेश करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है।

अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने से न केवल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ की गई मेहनत बेकार जा रही है, वहीं वर्तमान सरकार के समय में भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं। वर्तमान सरकार के शुरुआती छह महीनों में ही 29 दागियों को बचा लिया, जबकि पिछली सरकार द्वारा 2013 में पद के दुरुपयोग के नामजद 26 कार्मिकों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गई थी। *(रा.प., 23.07.14)*

भ्रष्टाचार कर रहा है जड़ें खोखली!

लोकायुक्त एस.एस कोठारी ने आमजन से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने का आह्वान करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के कारण समाज की नींव कमजोर हो रही है और यह विकास में बाधक बना हुआ है।

बांदीकुई में आयोजित जनसुनवाई के दौरान उन्होंने यह आह्वान करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति के आर्थिक रूप से मजबूत होने से सार्वजनिक जगहों पर उसका सम्मान किया जाता है। आवश्यक यह है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए। सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों को ईमानदारी से कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार से युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो शिकायत मय तथ्यों के साथ दर्ज कराएं। उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। *(दै.न., 06.09.14)*

कहां जाता है विकास का पैसा?

हमारे सिस्टम में सब जगह से लीकेज (भ्रष्टाचार) है। सरकार विकास के लिए ऊपर से पैसा डालती है नीचे से लीक हो जाता है। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने पाली जिले में आचार्य भिक्षु समाधि स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही।

उन्होंने कहा कि पाली जिले के ग्रामीण विकास के लिए पांच हजार करोड़ रुपए का बजट रखा है, जितना विकास कराना चाहते हो करवाएं। विकास में पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन दुःख होता है जितना पैसा दिया जाता है उतना विकास में लग नहीं पाता। पैसा कहां जाता है कोई नहीं जान पाता। हिन्दुस्तान से यह बीमारी खत्म हो जाए तो देश की तस्वीर दस साल में बदल जाएगी। *(दै.भा. एवं रा.प., 08.09.14)*

भ्रष्ट अफसरों पर शिकंजा कसे सरकार

राज्य विधानसभा में कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान सत्ता पक्ष के आधा दर्जन विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में सालों से एक ही सीट पर जमी नौकरशाही पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन पर तत्काल शिकंजा कसने की राज्य सरकार से पुरजोर मांग की।

भाजपा के अमृतलाल मीणा ने बहस के दौरान कहा कि उदयपुर में डिप्टी रजिस्ट्रार खुलेआम चौथवसूली कर रहे हैं। भाजपा के फूलसिंह मीणा ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में इन्दिरा आवास योजना में बिना हस्ताक्षर के मिलीभगत कर पैसे उठा लिए गए। भाजपा के रामलाल गुर्जर ने भीलवाड़ा डेयरी की जांच कराने जैसे अनेक मामले विधायकों ने उठाए हैं। उनका कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया अब ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए। *(दै.न., 22.07.14)*

चाल कछुए की, लेकिन फंसाए 'हाथी'

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई अन्य सालों की अपेक्षा धीमी रही, लेकिन बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होने से यह धीमी कार्रवाई छुप गई। साल की सबसे बड़ी कार्रवाईयों में अजमेर जिले के निलंबित जज अजय शारदा और कोटा एसपी सतवीर सिंह की गिरफ्तारी है।

इसी तरह कोटा, झुंझुनूं और अलवर के तीन डॉक्टरों व दो आरटीओ कार्यालयों में रुपए का खेल पकड़ने तथा 180 दिन में 10 करोड़ का कमीशन बटोरने वाले नगर निगम जयपुर के पूर्व सीईओ आईएएस लालचन्द असवाल, जयपुर नगर निगम के ही एक्सईएन पुरूषोत्तम जेसवानी, जोधपुर नगर निगम आयुक्त रामकिशोर माहेश्वरी को पकड़ना एसीबी की बड़ी कार्रवाई रही।

(दै.न., 09.09.14 एवं दै.भा., 27.09.14)

भ्रष्टों का बचाव करते हैं विभाग

भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी के आंकड़ों के अनुसार राजस्व विभाग के बाद सबसे ज्यादा कार्रवाई नगरीय विकास व स्वायत शासन विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों पर होती है। इनमें नगर निकाय के कर्मचारी सबसे आगे हैं।

रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने का मामला हो या पद के दुरुपयोग का एसीबी के चंगुल में फंसने के बाद विभाग अपने कर्मचारियों का बचाव करता है। एसीबी को विभाग के 42 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति का इंतजार है। लगभग सभी में एक बार मनादी आ चुकी है। मामले एसीबी ने विचार के लिए दुबारा भेजे हैं। *(रा.प., 11.08.14)*

लोकायुक्त को करें भ्रष्टाचार की शिकायत

सरकारी कार्यालयों द्वारा कार्य में देरी करने या भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायतें लोकायुक्त सचिवालय में की जा सकेगी। लोकायुक्त एस.एस.कोठारी ने इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में बोर्ड लगाए जाने के निर्देश दिए हैं।

निर्देशानुसार लोकायुक्त के कार्यक्षेत्र और प्रावधानों के बारे में जागरूकता लाने के लिए बोर्ड पर यह जानकारी प्रदर्शित होनी चाहिए कि सरकारी कार्यालयों में कार्य में देरी या भ्रष्टाचार से परेशान होने पर निष्पक्ष जांच के लिए लोकायुक्त के समक्ष शिकायत की जा सकती है। बोर्ड पर लोकायुक्त सचिवालय का पता, फोन नंबर, फैक्स, अंकित होना चाहिए। *(दै.न., 22.07.14)*

लोकायुक्त का पता
लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान, शासन सचिवालय परिसर, जयपुर-302005
फोन नंबरः 0141-2227145
फैक्सः 0141-2227083

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
जोधपुर	दीपक पंडत महेन्द्र कुमार	लिपिक, नगर निगम, जोधपुर कर्मचारी, नगर निगम, जोधपुर	50,000	दै.न., *05.07.14*
जालौर	छोगाराम सैन	रीडर, बागौडा तहसील, जालौर	17,500	दै.न., *05.07.14*
कोटा	जगदीशप्रसाद चौधरी	पटवारी, कनवास तहसील, बृजनगर	4,000	दै.न., *09.07.14*
जोधपुर	राजेन्द्र कुमार हंसा राम चौधरी	जेईएन, जोधपुर डिस्कॉम राजेन्द्र कुमार का निजी आदमी	30,000	दै.भा., *12.07.14*
जोधपुर	अणदाराम सिंघाड़िया	प्रबंधक, मरुधरा ग्रामीण बैंक, सावरिया, फलोदी	7,000	दै.भा. एवं दै.न., *18.07.14*
बूंदी	महेश जैन	कानूनगो, दबलाना, बूंदी	26,000	रा.प. एवं दै.भा., *21.07.14*
झुंझुनूं	बहादुर मल सैनी	वरिष्ठ लिपिक, विद्युत निगम कार्यालय, बबाई	5,000	दै.न. एवं दै.भा., *23.07.14*
जयपुर	मुकेश शर्मा ऋषिराज मीणा	लेखाकार, शिक्षा संकुल, फीस निर्धारण समिति व.लिपिक, शिक्षा संकुल,फीस निर्धारण समिति	10,000	रा.प. एवं दै.भा., *24.07.14*
पाली	राजूराम बामणिया	थाना प्रभारी उपनिरीक्षक, शिवपुरा थाना पाली	35,000	रा.प., *29.07.14*
जयपुर	बुद्धराम	एस एसआई, थाना माणक चौक, जयपुर	10,000	दै.भा. एवं रा.प., *08.08.14*
सीकर	नाथूराम महरानिया	डीएसपी, रींगस जिला सीकर	50,000	दै.भा., *08.08.14*
उदयपुर	सुरेश कुमार खटीक	एसएचओ, कुराबड़ थाने में पदस्त	25,000	रा.प. एवं दै.न., *12.08.14*
अलवर	हजारी सिंह चौहान	रेंजर (फॉरेस्टर), किशनगढ़वास	1,50,000	रा.प. एवं दै.भा., *13.08.14*
सिरोही	बालाराम लुहार पुरषोत्तम	सरपंच, ग्राम पंचायत सनपुर (सिरोही) सरपंच पुत्र, ग्राम पंचायत सनपुर (सिरोही)	15,000	रा.प., *18.08.14*
जयपुर	गोपालराम	एसआई, मानसरोवर थाना, जयपुर	15,000	रा.प., *23.08.14*
जोधपुर	रामकिशोर माहेश्वरी	आयुक्त, जोधपुर नगर निगम	35,000	रा.प., *23.08.14*
अलवर	मुखराज मीना लालाराम सैनी	जेईएन, विद्युत वितरण निगम कार्यालय माचेड़ी लाइनमैन, विद्युत वितरण निगम कार्यालय माचेड़ी	13,000	दै.न. एवं दै.भा., *02.09.14*
जयपुर	हीरालाल अग्रवाल	कार्यालय अधीक्षक, जयपुर डीआरएम ऑफिस	20,000	दै.भा. एवं रा.प., *03.09.14*
अजमेर	शिवराज सिंह	मीटर रीडर, अजमेर विद्युत वितरण निगम	10,000	दै.न., *12.09.14*

बन्द नहीं होगी मुफ्त दवा योजना

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि निःशुल्क दवा, जांच व पेंशन योजनाओं को बन्द नहीं किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा।

इससे पहले राज्य के चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ भी इस बारे में जनता को आश्वस्त कर चुके हैं। मुफ्त दवा योजना का लाभ केवल बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों को ही देने की लगाई जा रही अटकलों को इससे विराम लग गया है। उन्होंने बताया कि दवाओं की खरीद के लिए बजट जारी कर दिया गया है। अस्पतालों में दवाओं की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। *(दै.भा., 19.08.14, 10.09.14)*

प्रधानमंत्री जन-धन योजना शुरु

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से की गई घोषणा पर अमल करते हुए 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि योजना के अनुसार सरकार की ओर से देश के हर परिवार के लिए एक बैंक खाता खुलवाया जाएगा। साथ ही हर खाते के साथ एक डेबिट कार्ड और एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा।

उन्होंने योजना को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि इस योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य गरीबों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करते हुए आर्थिक छूआछूत को खत्म करना है। योजना के शुरू होते ही जनता ने योजना के तहत खाते खोलने में गहरी दिलचस्पी ली है और बैंकों में खाता खोलने की एक होड़ सी लगी है। *(दै.न., 26.08.14)*

भामाशाह योजना शुरू

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 15 अगस्त को उदयपुर में हुए राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में भामाशाह योजना की शुरूआत की। उन्होंने योजना के तहत आठ महिलाओं को स्मार्ट कार्ड देते हुए इस साल योजना के लिए 600 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर योजना पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्कीम है।

इस योजना से प्रदेश की एक करोड़ 50 लाख महिलाओं को मल्टीपर्पज स्मार्ट कार्ड के जरिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया के नाम से खुले खाते में राशि जमा होगी। महिला मुखिया के नाम से खुले बैंक अकाउंट से महिलाओं को ताकत मिलेगी। *(दै.भा., 17.08.14)*

श्री योजना में गुजरात मॉडल

ग्रामीण विकास के लिए श्री योजना को राज्य सरकार गुजरात की तर्ज पर लागू करने पर विचार कर रही है। ज्यादा आबादी वाले गांवों में योजना को उन्नत तरीके से चलाया जाएगा। योजना में आधारभूत ढांचा विकास के साथ ही बेहतर सेवा अदायगी पर पूरा जोर दिया गया है। गांवों में सेनिटेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी की व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमत पांडेय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में पांच हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को इस योजना में कवर किया जा रहा है। शेष गांवों को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा। योजना भरतपुर संभाग में लागू की जा चुकी है। शेष राज्य में इसे दो अक्टूबर से लागू किया जाएगा। *(दै.न.एवं दै.भा., 13.08.14)*

बिना भौतिक सत्यापन मिलेगी पेंशन

सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों में बढ़ती नाराजगी को देखते हुए राज्य सरकार ने जून से सितम्बर तक की पेंशन बिना भौतिक सत्यापन के जारी करने के आदेश दिए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों व कोषाधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

हालांकि जिन पेंशनधारियों का भौतिक सत्यापन हो चुका है, उन्हें रिपोर्ट के मुताबिक भुगतान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार की ओर से कराए जा रहे भौतिक सत्यापन के कारण जून 2014 से पेंशन नहीं मिल रही है। *(रा.प., 09.09.14)*

राजनीतिक दल आरटीआई में नहीं

केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक दल सूचना का अधिकार कानून के दायरे में नहीं हैं और सरकार इस पक्ष में नहीं है कि पार्टियां इस दायरे में आएं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया, इस कानून के तहत राजनीतिक दलों को लोक प्राधिकरण घोषित करने से उनका आंतरिक कामकाज बाधित होगा। राजनीतिक प्रतिद्वंदी इसका दुरुपयोग कर सकते हैं।

यू उठा था मुद्दाः केन्द्रीय सूचना आयोग ने कहा था कि कांग्रेस, भाजपा, माकपा, भाकपा, राकांपा व बसपा आरटीआई के तहत लोक प्राधिकरण है। इसलिए इन्हें लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। *(रा.प., 01.08.14)*

राज्य बजट है हमारी वार्षिक योजना

मौजूदा वित्तीय वर्ष में विकास, जन कल्याणकारी कार्य और आधारभूत संरचना निर्माण पर 69 हजार 820 करोड़ रुपए प्रदेश में खर्च होंगे। राज्य सरकार इसको मंजूरी के लिए केन्द्रीय योजना आयोग के पास भेजेगी।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसको मंजूरी दे दी है। इसका आकार पिछले वित्तीय वर्ष से 72 फीसदी अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक तिगुनी बढ़ोतरी आर्थिक सेवाओं के मद में की गई है। इसी मद में महत्वाकांक्षी भामाशाह योजना पर खर्च होगा। वार्षिक योजना विधानसभा से मौजूदा वित्तीय वर्ष का बजट स्वीकृत होने के बाद हुई है। इस कारण बजट और वार्षिक योजना के आंकड़ों में कोई अंतर नहीं है। *(रा.प., 10.09.14)*

चिंताजनक है बिजली चोरी-गोयल

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि राजस्थान में बिजली चोरी गंभीर समस्या है। इसे रोका जाना चाहिए। दिल्ली से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए देशभर के पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने पिछली सरकार का नाम लिए बिना कहा कि 2008 से 2013 के बीच चोरी के चलने 55 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है।

इससे बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ा है और खामियाजा बिजली उपभोक्ताओं को भी भुगतना पड़ता है। ऐसी स्थिति के चलते प्रदेश की मुख्यमंत्री और उनकी टीम उनके संपर्क में है। घाटे की कमी को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। प्रदेश की बिजली उत्पादन इकाइयों में कम उत्पादन के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए पॉवर लोड फैक्टर बढ़ाया जाएगा। केन्द्र सरकार बिजली पर खास योजना बना रही है साथ ही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना का कुछ अंश राज्यों को देने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा सौर ऊर्जा पैदा कर गांवों और ढ़ाणियों तक बिजली पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे।

(रा.प., 08.09.14)

सोलर लाइट खरीद की होगी जांच

राज्य सरकार प्रदेश की सभी 9 हजार 177 ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट खरीद की जांच कराएगी। खरीद प्रक्रिया में पैसे का गलत उपयोग पाए जाने पर उसकी तीन महीने में वसूली भी की जाएगी।

ग्रामीण विकास मंत्री गुलाबचन्द कटारिया ने विधानसभा में विधायक मोहनलाल गुप्ता के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यह जानकारी देते हुए कहा कि खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी में जितने भी लोग शामिल होंगे, उनको दण्ड दिया जाएगा। अनियमितताएं रोकने के लिए फिलहाल सोलर लाइट खरीद पर रोक लगा दी गई है। राज्य के 19 जिलों की प्राप्त सूचना के आधार पर 1182 ग्राम पंचायतों में अधिक दर पर सोलर लाइटें खरीदी गई हैं। इससे प्रथम दृष्टया 11 करोड़ 29 लाख रुपए अधिक खर्च किए गए हैं। *(दै.न., 24.07.14)*

सोलर प्लांट लगाने को केन्द्र तैयार

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यदि राजस्थान सरकार बिजली प्रोजेक्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराने को तैयार हो तो केन्द्र राजस्थान में सौर ऊर्जा का अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट लगाने को तैयार है। जैसे ही राज्य सरकार जमीन चिन्हित कर बता देगी, केन्द्र सरकार प्लांट लगा देगी।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार जयपुर जिले के सांभर में सोलर प्लांट लगाने के मामले में राज्य सरकार की अनुमति का इंतजार कर रही है। राज्य सरकार द्वारा सांभर या अन्य स्थान पर मरुस्थलीय जमीन चिन्हित करने और केन्द्र को उसकी क्लियरेंस मिलते ही प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में गांवों और ढ़ाणियों तक बिजली मुहैया कराने के लिए भी योजना बनाई जा रही है।

(दै.भा.एवं दै.न., 08.09.14)

बिजली शिकायतों में भारी इजाफा

राज्य की बिजली कंपनियों के खिलाफ विद्युत लोकपाल को की गई शिकायतों में काफी इजाफा हुआ है। पिछले पूरे साल में जितनी शिकायतें दर्ज कराई गई थी, उससे ज्यादा शिकायतें इस साल साढ़े तीन महीने की अवधि में ही आ चुकी हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें बिलों में गड़बड़ियों को लेकर है।

विद्युत लोकपाल डी.आर. माथुर ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान उन्हें कंपनियों के खिलाफ 62 शिकायतें मिली थीं, जबकि इस साल एक अप्रेल से लेकर 17 जुलाई तक 63 शिकायतें मिल चुकी हैं। इनमें से 39 शिकायतों पर फैसला सुनाया जा चुका है और शेष की प्रकिया जारी है। जिला उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए तीन स्तरीय सिस्टम होता है। जिन उपभोक्ताओं की शिकायतों का वहां निराकरण नहीं हो पाता वे ही लोकपाल के पास दर्ज होती हैं। *(दै.भा., 21.07.14)*

हर यूनिट पर ढ़ाई रुपए का घाटा

राजस्थान में बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम ने कहा है कि मौजूदा हालात में बिजली दरों में बढ़ोतरी करना जरूरी है, क्योंकि हर यूनिट बिजली पर उन्हें तकरीबन ढ़ाई रुपए का घाटा हो रहा है। डिस्कॉम ने वादा किया है कि अगले एक साल में खर्च घटाने व बेहतर कार्यप्रणाली अपनाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे, जिससे अगले साल दरों में ज्यादा बढ़ोतरी की जरूरत नहीं पड़ेगी।

जयपुर, जोधपुर डिस्कॉम व अजमेर डिस्कॉम द्वारा दाखिल एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट (एनआरआर) पर राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा दो दिवसीय जन-सुनवाई हुई आयोग द्वारा अब सितम्बर के आखिर तक फैसला लिए जाने की संभावना है, जिसके बाद बिजली की बढ़ी हुई दरें लागू की जाएगी। डिस्कॉम ने अपने एआरआर में बिजली दरों में 22.5 फीसदी बढ़ोतरी की मांग की है। *(दै.भा., 12.09.14)*

करोड़ों की बिजली चोरी पकड़ी

जयपुर डिस्कॉम की सतर्कता शाखा एवं ओएण्डएम विंग द्वारा विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने के लिए विशेष सतर्कता जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र के प्रत्येक जिले में विद्युत चोरी बाहुल्य क्षेत्रों को चिन्हित कर अत्यधिक छीजत वाले फीडरों पर सतर्कता दलों द्वारा जांच की जा रही है।

बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष के शुरू के चार महीनों में ही सतर्कता दलों द्वारा 20461 आकस्मिक जांचें की गई जिसमें 13791 मामले विद्युत चोरी के पकड़े गए हैं। जिनसे 21.41 करोड़ रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया है।

(दै.न. एवं दै.भा., 06.08.14)

मनरेगा के तहत रिचार्ज होगा भू-जल

प्रदेश के डार्क जोन घोषित क्षेत्रों में बसे गांवों में पीने योग्य पानी का संग्रहण कर भूजल को रिचार्ज किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा गुजरात की तर्ज पर गांवों में जल संग्रहण की योजना तैयार की जा रही है। जल्द ही जिला कलेक्टरों के माध्यम से तैयार प्लान को मंजूरी दे दी जाएगी।

ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की प्लानिंग इस तरह की जाएगी कि जरूरत पड़ने पर गांव को कम से कम एक साल के लिए पीने योग्य पानी की सप्लाई हो सके। यदि गांव के पास नदी या नहर क्षेत्र है तो जल पुनर्भरण ढांचा उसके नजदीक बनाया जाएगा। गांवों में बनने वाले इन ढांचों में बारिश के पानी को स्टोर करने की व्यवस्था की जाएगी।

(दै.न., 19.08.14)

दूषित पानी तो नहीं पी रहे?

जलदाय विभाग लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए इसमें ब्लीचिंग पाउडर डालता है, लेकिन पाउडर ही तय मानकों के अनुरूप नहीं हो तो पानी की शुद्धता पर सवाल खड़ा होता है। हैरत की बात यह है कि यही ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर जयपुर शहर में पानी की आपूर्ति की जा रही है।

दरअसल विभाग द्वारा खरीदे गए 25 हजार किलो ब्लीचिंग पाउडर की गांधी नगर स्थित रेफरल लेबोरट्री में दो बार जांच कराई गई तो दोनों ही बार नमूनों में क्लोरीन तय मानक से कम पाया गया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के गेस्ट्रोलोजिस्ट डॉ. अशोक झाझड़िया के अनुसार घरों में आपूर्ति होने वाला पानी पूरी दिनचर्या में हर स्तर पर काम आता है। यदि लगातार अशुद्ध व कम गुणवत्ता वाला पानी का इस्तेमाल किया जाए तो पेट संबंधी बीमारियां पीलिया, उलटी-दस्त आदि हो सकते हैं। *(रा.प., 24.09.14)*

नहीं हुआ पेयजल लाइनों का सर्वे

जयपुर शहर में चारदीवारी और बाहरी इलाकों में बढ़ रही दूषित पानी की समस्या के बावजूद जलदाय विभाग को इससे सरोकार नहीं है। शहर में दूषित पानी की वर्तमान समस्या को नकारते हुए विभाग का मानना है कि शहर में पेयजल प्रदूषण के मात्र 17 संवेदनशील जोन है।

यह जोन भी आठ साल पहले विभाग के द्वारा ही चिन्हित किए गए थे। जबकि वर्तमान में चारदीवारी क्षेत्र में ही हर गली में सैकड़ों ऐसे प्वाइंट मिल जाएंगे जहां से सीवर का पानी पेयजल लाइन में मिलने का अंदेशा है। विभाग के अधिकारियों का यह भी मानना है कि सर्वे के दौरान जर्जर पेयजल लाइन मिली तो उसमें सुधार कराया जाएगा। विभाग द्वारा आठ साल पहले चिन्हित कराए गए जोन में अभी भी दूषित पेयजल सप्लाई हो रहा है।

(रा.प., 19.08.14, 27.08.14)

बहा देते है 100 करोड़ का पानी

जयपुर में 110 किलोमीटर दूर बीसलपुर बांध से लाया गया महंगा पानी रोज 14 से 16 करोड़ लीटर बेकार बह जाता है। पीने के लिए साफ कर लाया गया करीब 100 करोड़ रुपए की लागत का पानी हर साल घरों तक पहुंचता ही नहीं है। सरकार को पानी पर प्रति किलोलीटर 16 रुपए का खर्च आ रहा है।

वर्ष 2010 में शहर को 24 घंटे पानी की आपूर्ति का सपना दिखाया गया था। अब हकीकत सामने आई है कि सालाना 100 करोड़ रुपए के पानी की बर्बादी को रोके बिना 24 घंटे पानी देना संभव नहीं हो सकता। अब जलदाय विभाग की प्लानिंग जिस दिशा में चल रही है उससे तो लगता है कि अगले 10 साल में भी पूरे जयपुर शहर को 24 घंटे पानी नहीं मिल पाएगा। *(दै.भा., 22.08.14)*

पानी के आधे नमूने फेल

जयपुर सहित प्रदेश के 10 जिलों की जनता को जलदाय विभाग की पेयजल लाइनों में गंदा पानी पिलाया जा रहा है। खुद जलदाय विभाग की ओर से पिछले महीने लिए गए पानी के जांच नमूनों में से 50 फीसदी से भी ज्यादा कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। इससे विभाग के अधिकारियों के उस दावे की पोल खुल गई है, जिसमें उन्होंने राजधानी में पानी को प्रदूषित नहीं होने का दावा किया था।

अधिकारियों का कहना था कि शहर में प्रदूषित पेयजल की समस्या नियंत्रण में है। जबकि जयपुर में ही 149 नमूनों में से 45 जांच नमूने फेल पाए गए हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि पानी आपूर्ति केन्द्र पर अवशेष क्लोरीन पाया गया लेकिन उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचते-पहुंचते उसमें यह अवशेष पूरी तरह समाप्त हो गए। *(रा.प., 07.09.14)*

बिजली खर्च बदलेगा पानी की दरें

प्रदेश में पेयजल की दरों में प्रस्तावित फेरबदल में बिजली की बढ़ती दरें बड़ी भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भले ही हाल के बजट में पेयजल की दरों को तर्कसंगत बनाने की घोषणा की हो, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री के समक्ष दिए गए प्रजेन्टेशन में बिजली खर्च का हवाला देते हुए दरों में फेरबदल की भूमिका बना चुके हैं।

रिपोर्ट में वर्ष 1997 से लेकर अब तक पेयजल के ऑपरेशन एंड मेन्टिनेंस में बिजली दरों में 158 प्रतिशत की बढ़ोतरी को आधार बना कर पानी की दरों को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता जताई गई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 में पेयजल को घरों तक पहुंचाने में ऑपरेशन एण्ड मेन्टिनेंस के पेटे 994.55 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें 545.36 करोड़ रुपए यानी 55 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ बिजली और 377 करोड़ रुपए वेतन आदि पर खर्च था। *(रा.प., 24.07.14)*

राजस्व मिला सिर्फ 18 प्रतिशत

पिछले वित्तीय वर्ष 2013-14 में 994.55 करोड़ रुपए के खर्च में से विभाग को सिर्फ 177.92 करोड़ रुपए का ही राजस्व प्राप्त हो पाया, जो लगभग 18 फीसदी है। जबकि बिजली खर्च ही इस राजस्व की तुलना में तीन गुणा हो गया।

'नई रोशनी' परियोजना से महिलाएं होंगी सशक्त

गरीब और वंचित वर्ग की महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ कर उन्हें सशक्त एवं जागरूक बनाया जाना आवश्यक है। इससे महिलाएं विभिन्न बंधनों से मुक्त हो स्वयं के तथा समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

यह विचार भीलवाड़ा जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्टर गिरीराज वर्मा ने 'कट्स' मानव विकास केन्द्र चित्तौड़गढ़ द्वारा भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय के सहयोग से संचालित 'नई रोशनी अल्पसंख्यक महिला नेतृत्व विकास' परियोजना के शुभारंभ बैठक को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। बैठक में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उमरदराज पठान ने जिले में महिलाओं की स्थिति एवं बैठक के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों और महिलाओं ने भाग लिया।

परियोजना के तहत भीलवाड़ा जिले के पांच क्षेत्रों की 125 अल्पसंख्यक महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्हें गृह प्रबंधन, महिला अधिकारों, स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, जीवन कौशल जैसे कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर सशक्त और सक्षम बनाया जाएगा। साथ ही सरकार द्वारा उनके हितों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाकर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा।

बनेगा महिला टेक्नोलॉजी पार्क

महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जयपुर में जल्द ही ग्रामीण महिला प्रोद्योगिकी पार्क बनेगा। पार्क में सात हजार महिलाओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए केन्द्र सरकार के विज्ञान व प्रोद्योगिकी विभाग ने सीतापुरा स्थित जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी को स्वीकृति प्रदान की है।

पार्क विश्वविद्यालय परिसर में बनाया जाएगा। सरकार इसके लिए 1.25 करोड़ रुपए लगाएगी। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर भी पैसा लगाएगा। इस प्रोजेक्ट में सांगानेरी प्रिंट, जवाहरात, कढ़ाई, ज्वैलरी डिजाइन जैसी अनेक स्थानीय कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं का चयन अनुभव और दक्षता को ध्यान में रख कर किया जाएगा। *(रा.प., 08.07.14)*

बिना मां के बच्चों को मदर मिल्क

प्रदेश के जे.के. लोन अस्पताल में अब प्रसूताओं के बीमार होने और बिना मां के बच्चों के नवजात बच्चों को निःशुल्क मां का दूध मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए अस्पताल में मदर मिल्क बैंक बनाया जाएगा। संभावित गर्भवती महिलाओं व प्रसूताओं को बैंक में दूध डोनेट करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, साथ ही दूध को मिल्क बैंक में संरक्षित रखा जाएगा।

यह जानकारी चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने देते हुए बताया कि इंडो-नार्वे विनिमय कार्यक्रम के तहत यह योजना शुरू की जा रही है और इसके लिए सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। *(दै.न., 08.08.14)*

महिला अत्याचार का बढ़ता ग्राफ

राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का ग्राफ दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। इस बात का खुलासा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2013 के जारी किए गए आंकड़ों में किया है। इन आंकड़ों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की दर देखी जाए तो दिल्ली पहले, असम दूसरे और त्रिपुरा तीसरे स्थान पर है।

यदि दर्ज मामलों के आधार पर नजर डाली जाए तो भी राजस्थान चौथे स्थान पर है। वर्ष 2013 में देश के प्रमुख शहरों में दुष्कर्म मामले में जयपुर तीसरे स्थान पर है। सबसे ज्यादा दुष्कर्म के मामले दिल्ली में और उसके बाद मुम्बई में सामने आए हैं। दिल्ली शहर में सबसे ज्यादा 1380, मुम्बई में 391 और जयपुर में 192 मामले दर्ज हुए हैं। *(दै.न., 03.07.14)*

बेटी बचाओ अभियान के लिए प्रकोष्ठ

प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान के तहत अलग से प्रकोष्ठ गठित कर सभी जिलों में सघन अभियान संचालित किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने राजधानी स्थित सीटी पैलेस में इस अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग की ब्रांड अम्बेसडर एवं विधायक दीया कुमारी के साथ बैठक में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि कन्या जन्म पर अभिभावकों को राज्य सरकार की ओर से बधाई सन्देश भेजने, भ्रूण लिंग परीक्षण पर प्रभावी रोकथाम एवं सोनोग्राफी केन्द्रों की नियमित जांच के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। *(रा.प., 08.08.14)*

कॉलेज छात्राओं को मिलेगी स्कूटी

राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ा वर्ग (गुर्जर, बंजारा, गाड़िया लुहार, रेबारी, राइका) के लिए देव नारायण योजना के तहत संचालित विभिन्न कार्यक्रम के लिए 170 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया है। इसके तहत राजस्थान बोर्ड परीक्षा में मैरिट के आधार पर राजकीय कॉलेजों में पढ़ रही छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूटी दी जाएगी।

स्कूटी के लिए सीनियर सैकण्ड्री बोर्ड परीक्षा में मेरिट के आधार पर छात्राओं का राजकीय कॉलेजों में नियमित रूप से अध्ययनरत होना जरूरी होगा। ऐसी 1000 छात्राओं को हर साल निःशुल्क स्कूटी मिलेगी।

(दै.भा. एवं रा.प., 11.09.14)

साकार हो 'स्वच्छ भारत' का सपना

भारत को स्वच्छ बनाने के लिए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय तेजी से जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की पहल को आगे बढ़ाते हुए मंत्रालय ने नागरिकों से आह्वान किया है कि शौचालय बनाने के लिए वे स्कूल तलाशें।

सहूलियत के लिए मंत्रालय ने ऐसे स्कूलों की सूची अपनी वेबसाइट पर जारी की है जहां शौचालय नहीं है या खस्ताहाल हैं।

(रा.प., 19.08.14)

सड़क सुरक्षा

सड़क दुर्घटना में बच्चे की मौत तो सात साल की कैद

देश में हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इनमें से करीब एक लाख चालीस हजार लोग मौत के शिकार बन जाते हैं। मद्देनजर केंद्र सरकार यातायात के नियमों को सख्त करने जा रही है। इसके लिए 'सड़क सुरक्षा एवं यातायात विधेयक 2014' का मसौदा तैयार किया गया है। सरकार ने इस पर प्रतिक्रियाएं मांगी हैं। इस विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। विधेयक के कुछ मुख्य प्रावधान निम्नांकित है :

- मसौदे के मुताबिक 'मोटर व्हीकल रेग्यूलेशन एंड रोड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया' नाम की स्वतंत्र एजेंसी भी होगी। ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली को भी सिंगल विंडो किया जाएगा।
- विधेयक में सड़क दुर्घटना में बच्चे की मौत पर तीन लाख रुपए का जुर्माना और कम से कम सात साल की जेल का प्रावधान किया गया है।
- सिग्नल तीन बार तोड़ने पर 15 हजार रुपए जुर्माना, एक माह लाइसेंस रद्द तथा ड्राइविंग का दोबारा अनिवार्य प्रशिक्षण । लापरवाही भरी ड्राइविंग पर एक लाख रुपए तक जुर्माना व छह माह से एक साल तक की कैद और लाइसेंस रद्द।
- नशे में ड्राइविंग करते पहली बार पकड़े जाने पर 15 हजार रुपए का जुर्माना या चार माह की कैद या दोनों और छह माह तक लाइसेंस निलंबित। दोबारा पकड़ा तो लाइसेंस रद्द, 30 दिन तक वाहन जब्त।
- स्कूल बस ड्राइवर होने पर 50 हजार रुपए जुर्माना, तीन साल की जेल। ड्राइवर की उम्र 18-25 साल तो तुरंत लाइसेंस रद्द।

(रा.प., 14.09.14)

जन स्वास्थ्य

गरीब मरीज भी दिखा सकेंगे विशेषज्ञ को

गरीब व असहाय मरीज भी प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों को निःशुल्क दिखा सकेंगे। एसएमएस ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में पिछले दिनों हैल्थ लाइन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विहिप अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि काफी गरीब और असहाय मरीज गंभीर बीमारी होने पर भी चिकित्सकों को नहीं दिखा पाते। वे सोचते हैं कि यदि किसी डॉक्टर को दिखाया तो वह बीमारी बता देगा और फिर इलाज लेना मुश्किल होगा, लेकिन उनको यह सोच दरकिनार करनी होगी। इसके बाद ही उनका इलाज संभव हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि यह सेवा गरीब मरीजों के लिए काफी लाभदायक होगी और वे अच्छे विशेषज्ञों को भी दिखा सकेंगे। मरीजों की शुगर, हीमोग्लाबिन और वजन जांच के लिए हैल्थ एंबेसडर सेवा सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत वॉलिंटियर बनाए जाएंगे और वे मंदिरों, पार्कों में आने वाले लोगों की जांच कर उन्हें बीमारियों के प्रति जागरूक करेंगे। उन्होंने अधिक से अधिक चिकित्सकों को इस सेवा से जुड़ने को प्रेरित किया। कार्यक्रम में डॉ. राम गोयल, डॉ. अशोक शारडा, डॉ. सर्वेश जोशी, डॉ. एमजे स्वर्णकार आदि उपस्थित थे।

क्या है हैल्थ लाइन

हैल्थ लाइन सेवा का नम्बर 18602333666 है। इस नम्बर पर फोन कर मरीज अपनी बीमारी बता सकेगा। यहां कंसल्टेंट मरीज को विशेषज्ञ डॉक्टर के बारे में बताएगा और मरीज का अपॉइंटमेंट करेगा। डॉक्टर के बताये समयानुसार मरीज को दिखाने का समय देगा। इसके बाद मरीज उस विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखा सकेगा।

(दै.भा., 21.07.14)

निवेशक शिक्षा

बाजार की अनियमितता रोके सेबी

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्तीय बाजार की विनियामक संस्थाओं के नियम बनाने की प्रक्रिया और अन्य कार्यों में अधिक पारदर्शिता पर बल देते हुए शेयर बाजार नियामक सेबी से कहा कि वह बाजार में अनियमितताएं रोकने के लिए ज्यादा सतर्कता बरते। उन्होंने सेबी को बाजार के प्रति खुदरा निवेशकों का आकर्षण बढ़ाने उनकी शिकायतों के निवारण के उपायों पर खास ध्यान देने को कहा है।

वित्त मंत्री ने सेबी निदेशक मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए यह कहा। बैठक के बाद सेबी के चेयरमैन यू.के.सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा कि वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में पूंजी बाजार से संबंधित घोषणाओं को लागू करने के बारे में भी चर्चा की और देश में निवेश के वातावरण का जायजा लिया।

वित्त मंत्री बनने के बाद सेबी बोर्ड के साथ जेटली की यह पहली बैठक थी। बैठक में सेबी के निदेशक मंडल ने प्रस्तावित रीयल एस्टेट निवेशन्यासों के दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया, जिनकी अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। जेटली ने बोर्ड के सदस्यों के साथ वित्तीय क्षेत्र कानून सुधार आयोग की सिफारिशों के संबंध में भी चर्चा की।

(दै.भा., 11.08.14)

दूरसंचार सेवाएं

कॉल दरें हो सकती हैं कम

दूरसंचार नियामक ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को बिना नीलामी के बेचे गए स्पेक्ट्रम को भी साझा करने की अनुमति देने की सिफारिश की है। इससे भविष्य में काल दरें काफी सस्ती होने की उम्मीद जगी है।

ट्राई ने इस साल आर्थिक समीक्षा में दिए गए सुझावों के अनुरूप अपनी सिफारिश में कहा है कि 1658 करोड़ रुपए की पुरानी दरों पर या बिना नीलामी के बेचे गए स्पेक्ट्रम को साझा करने की अनुमति देने से इन कंपनियों की परिचालन लागत काफी कम हो जाएगी। इससे कंपनियां मोबाइल सेवाओं की कॉल दरों में अच्छी कटौती कर सकेगी।

(दै.भा., 22.07.14)

उपभोक्ता फैसले

कॉलेज पर भारी पड़ा छात्र को परीक्षा में नहीं बिठाना

डॉ. राधाकृष्णन पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के छात्र महेन्द्र कुमार शर्मा ने जिला उपभोक्ता मंच जयपुर (द्वितीय) में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया।

परिवाद में कहा गया कि शैक्षणिक सत्र 2012-13 में वह डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस में द्वितीय वर्ष का छात्र था। उसकी 22 अप्रेल 2013 से परीक्षाएं शुरू हुई और उसने तीन पेपरों की परीक्षा दे दी थी, लेकिन 27 अप्रेल, 2013 को परीक्षा केन्द्र पर उसे यह कह कर परीक्षा देने से रोक दिया गया कि उसकी फीस बाकी है। उसने कालेज प्रशासन को बताया कि 16 अक्टूबर 2012 को कॉलेज फीस व बस फीस सहित कुल 27 हजार रुपए जमा करा दिए थे। इसके बावजूद कॉलेज के प्रिंसीपल ने कहा कि वह कॉलेज चेयरमैन की अनुमति से ही परीक्षा में बैठ सकता है। इसपर उसने कॉलेज चेयरमैन से परीक्षा में बैठने की अनुमति भी ले ली, लेकिन कॉलेज के प्रिंसीपल और परीक्षा अधीक्षक ने उसे परीक्षा में शामिल नहीं किया।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच जयपुर (द्वितीय) ने प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज प्रशासन को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए डॉ. राधाकृष्णन पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रशासन को आदेश दिया कि महेन्द्र कुमार शर्मा को 50 हजार रुपए का हर्जाना एक माह की अवधि के भीतर अदा करे। *(दै.भा., 02.07.14)*

रेलवे अदा करे एक लाख रुपए का हर्जाना

वरिष्ठ नागरिक राजमल जैन व पांच अन्य यात्रियों ने उत्तर-पश्चिम रेलवे के खिलाफ उपभोक्ता मंच जयपुर में परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में मंच को बताया गया कि उन्होंने 24 दिसम्बर 2010 को उम्मेद शिखरजी जाने के लिए 28 अक्टूबर को जयपुर से पार्श्वनाथ तक का ई-टिकट बुक कराया था। विभाग ने टिकट को आरएसी श्रेणी में रखा था। टीटीए ने उन्हें आश्वासन दिया कि यात्रा के लिए उन्हें पूरी सीट दी जाएगी। परिवाद में यह भी कहा गया कि यात्रा के दिन टीटीए मनमानी करते हुए दूसरे नये यात्रियों को बर्थ मुहैया करा रहा था, जबकि उन्हें बर्थ नहीं दी गई। इससे उन्हें 1150 किलोमीटर की यात्रा को बैठे-बैठे ही पूरा करना पड़ा, नतीजतन उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया।

मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता मंच ने यात्रियों को आश्वासन देने के बाद भी पूरी सीट मुहैया नहीं कराने को सेवा दोष माना और उत्तर-पश्चिम रेलवे पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके अलावा मंच ने ग्यारह हजार रुपए की अतिरिक्त राशि परिवाद व्यय के तौर पर अदा करने को कहा है। मंच ने रेलवे को यह भी आदेश दिए है कि इस राशि की वसूली संबंधित टीटीए से की जाए। *(रा.प. एवं दै.न., 26.09.14)*

खास समाचार

विद्युत सेवाओं में दोष तो मिलेगा हर्जाना

हाई वोल्टेज से बिजली उपकरण फूंके या घोषित समय से अधिक कटौती हो या फिर आपूर्ति बाधित हो तो इसे प्रदेश की बिजली कंपनियों का सेवा दोष माना जाएगा। प्रदेश की बिजली कंपनियों को इसके लिए उपभोक्ताओं को हर्जाना देना होगा।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने स्टेण्डर्ड ऑफ परफोरमेंस (एसओपी) में हर्जाना देने को लेकर अलग से नोटिफिकेशन जारी किया है। अब उपभोक्ता इस प्रवधान के हिसाब से बिजली कंपनियों पर सेवादोष की स्थिति में दावा पेश कर सकेंगे। आयोग ने बिजली से जुड़ी अलग-अलग सेवाओं के निस्तारण के लिए भी समयबद्ध जार्च जारी किए हैं। आयोग ने निर्धारित समय पर बिजली कंपनियों द्वारा इनकी पालना नहीं किए जाने पर उपभोक्ताओं को 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए का हर्जाना देने के भी एसओपी में प्रावधान किए हैं। *(रा.प., 02.10.14)*

ऐसे होगी नुकसान की भरपाई

- *पंखा मिक्सी व ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर 500 रुपए कलर टीवी, सेमी ऑटो वॉशिंग मशीन, फ्रिज पर 1000 रुपए,ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कम्प्यूटर, एसी पर 2000 रुपए का हर्जाना मिलेगा।*
- *उपभोक्ता को 24 घंटे से पहले सूचना, अति आवश्यक स्थिति में 10 घंटे तक कटौती, इसमें शाम छह बजे आपूर्ति शुरू कर दी जाए। ऐसा नहीं करले पर एलटी लाइन में 50 रुपए व एच टी लाइन में 100 रुपए।*
- *शहर में 16 घंटे, कस्बे में 36 घंटे व ग्रामीण इलाकों में 72 घंटे , नहीं तो एलटी लाइन वाले उपभोक्ताओं को 100 रुपए व एचटी लाइन पर 300 रुपए का हर्जाना।*

उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

'कट्स' सेंटर फॉर कन्ज्यूमर एक्शन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (कट्स कार्ट) द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण करने, शिकायतों से संबंधित सूचना एवं सलाह सेवाएं देने के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया हुआ है। कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत या समस्याओं के बारे में स्वयं व्यक्तिश कार्यालय समय में डी-218, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर स्थित कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है अथवा नीचे लिखे फोन, फैक्स व ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रेषित कर सकता है।

फोन: 141-2282823, 2282482, 5133259, फैक्स: 141-4015395
ईमेल: cart@cuts.org, वेबसाइट: www.cuts-international.org

कट्स कार्ट

स्त्रोत: रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, बी.एल.: बिजनेस लाइन

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोन: 91.141.513 3259 फैक्स: 228 2485, टेलीफैक्स: 401 5395, ई-मेल: cart@cuts.org, वेबसाईट: www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।